

अपराह्न 12.14 बजे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरिंग कर्मचारियों के वेतनमान कम किये जाने के बारे में याचिका

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (डेंकानाल): मैं श्री पी. एन. कोहली, प्रेज़ीडेंट, रेडियो और टेलीविजन इंजीनियरिंग कार्यकारी एसोसिएशन, पोस्ट बाक्स 422 नई दिल्ली और अन्यो द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरिंग कर्मचारियों के वेतनमान कम कर दिये जाने के बारे में हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.14^{1/2} बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

माले में हुआ नौवां सार्क शिखर सम्मेलन

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): मैं 12 से 14 मई, 1997 को माले में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के नौवें शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के संबंध में सदन के समक्ष अपनी ओर से वक्तव्य देते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। हाल के वर्षों में सार्क के सात सदस्य देशों में सहयोग बढ़ा है और इस सम्मेलन ने संगठन की ताकत को पुनः सिद्ध कर दिया है। माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं इस सम्मेलन के दौरान हुई मुख्य बातों का सारांश प्रस्तुत करना चाहूँगा।

सार्क के पिछले एक निर्णय के अनुसार अधिमानतः वर्ष 2000 तक और हर हालत में 2005 ई. तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के लिए कार्य किया जाना था। नौवें सम्मेलन में अब इस बात पर सहमति हुई कि साफ्टा को वर्ष 2001 तक कार्यान्वित कर लिया जाए, इस प्रकार यह अंतिम लक्ष्य चार वर्ष पहले पूरा हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सदस्य देशों के बीच तेजी से हो रहे आर्थिक कार्यकलाप को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ते हुए भावनात्मक लगाव का द्योतक है।

सार्क के लिए दूर दृष्टि विकसित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के एक दल के गठन के संबंध में लिया गया निर्णय एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था। राज्य प्रमुखों के बीच यह आम राय थी कि सार्क अब प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप सुदृढ़ करने की स्थिति में आ गया है जिसके लिए एक कार्यसूची तैयार की जानी चाहिए।

बैठक में दक्षिण एशिया में उप क्षेत्रीय सहयोग का प्रश्न उभर कर आया। इस शिखर सम्मेलन से पूर्व उप क्षेत्रीय सहयोग और सार्क के क्षेत्रीय ढांचे के बीच उपयुक्त संबंधों के बारे में व्यक्त किए गए विचारों में कुछ भिन्नताएं थीं। जबकि शुरू से ही हमारी वरीयता यह थी कि उप क्षेत्रीय सहयोग सार्क के भीतर, विशेषतौर पर इसके चार्टर के अनुच्छेद सात के उपबंधों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। कुछ अन्य देशों ने शुरू में यह महसूस किया कि उप क्षेत्रीय प्रबंधों को सार्क के बाहर रखना उपयुक्त होगा। प्रसन्नता की बात यह है कि यह मसला सभी पक्षों की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार हल कर लिया गया। यह सहमति हुई कि उप क्षेत्रीय सहयोग की विशिष्ट परियोजनाएं सचिवालय द्वारा विकसित और संसाधित की जाएं और इनके कार्यान्वयन से पूर्व सार्क की स्थापित प्रक्रिया द्वारा अन्तर सरकारी तौर पर उन्हें समर्थन दिया जाए। इससे सभी सदस्यों के लिए नहीं बल्कि कुछ सदस्यों की उपयोगी परियोजनाओं, जिनमें नेपाल के प्रस्ताव पर आभारित बंगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल सहित चतुरपक्षीय प्रयास शामिल हैं, इस तरह से विकसित की जानी है जिससे सार्क की गतिविधियों में और अधिक लोच आएगा तथा ये गतिविधियाँ संवर्धित होंगी।

शिखर सम्मेलन में समाज में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित समस्याओं, विशेष तौर पर विभिन्न कठिन परिस्थितियों में बालिकाओं की समस्याओं पर अधिक जोर दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि 2000-2010 के दशक को बच्चों के अधिकारों के सार्क दशक के रूप में मनाया जायेगा। सार्क महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान देगा।

सार्क कार्य कलापों को दूरवर्ती शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करके बढ़ाया जाएगा और खुले विश्वविद्यालयों और दूरवर्ती शिक्षण संस्थानों को खुले विश्वविद्यालयों के संकाय के निर्माण की सम्भावनाओं के साथ क्षेत्र के बाहर प्रसार किया जाएगा।

पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी तथा उन पहलुओं को शामिल किया गया जिसमें वायु और जल प्रदूषण के सामान्य न्यूनतम मानक विकसित करने, सीमा पार जैव विविधता संरक्षण और वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के अवैध दुर्व्यापार को रोकने संबंधी सार्क अभिसमय तैयार करना जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। इसके बाद सहयोग के इस क्षेत्र की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए सार्क पर्यावरण मंत्री साल में एक बार बैठक किया करेंगे।

सार्क अन्तर-यात्रा के लिए अपेक्षित वीसा की शर्तों में प्रगामी छूट की प्रक्रिया जारी रही तथा कुछ नई श्रेणियों में अब से छूट दी जाएगी। नई श्रेणियों में सार्क देशों के सभी मंत्रिमण्डलीय सदस्य, गैर सरकारी संगठनों के शीर्ष निकायों के प्रमुख तथा बहुत से अन्य प्रमुखों को शामिल किया जाएगा।

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

सार्क क्षेत्र के अलावा व्यावसायिक संगठनों और स्वैच्छिक समूहों के मध्य सहयोग संवर्धित करने के उद्देश्य से सार्क मान्यताप्राप्त निकायों की एक नयी श्रेणी के सृजन के बारे में सहमति हुई जो सार्क सचिवालय के साथ सहयोगी और उत्साहवर्धक भूमिका अदा करने के लिए ऐसे समूहों के साथ समन्वित कार्य करने में समर्थ होगा। इस निर्णय से क्षेत्र व्यापी सहयोग और लोगों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के नए माध्यमों को सृजित करने में सुविधा मिलेगी।

इस क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की प्रगति की निगरानी के सार्क तंत्र के संदर्भ में इस बात पर सहमति हुई कि वित्त और योजना मंत्रियों की तृतीय बैठक शीघ्र ही होगी। इस वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने में लक्ष्य समूहों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और 1997 को 'सार्क सहभागी शासन वर्ष' के रूप में नामित किया गया है।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि शिखर सम्मेलन में सदस्य राज्यों के प्रस्ताव बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक थे जो सार्क के भविष्य के लिए शुभ संकेत हैं। सदस्य राज्यों के भीतर सार्क के कार्यों को समृद्ध बनाने और इसे हर वर्ष और सुदृढ़ बनाने की ठोस इच्छा बलवती है। घनिष्ठ सहयोग कायम करने के बढ़ते हुए वातावरण को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सार्क नेताओं के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक परामर्श लाभदायक होगा।

इस सार्क शिखर सम्मेलन की सम्बद्ध सकारात्मक विशेषताओं से एक विशेषता राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों और विदेश मंत्रियों को इस बात का अवसर प्रदान करना है कि वे आपस में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में बातचीत का आदान दान करें। मैंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण भावना में अन्य सभी राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के साथ बातचीत की।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी मुलाकात ने काफी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। मुझे उनसे मुलाकात करने तथा अपने द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श करने में प्रसन्नता हुई। यह हमारे दोनों देशों के बीच ढांचागत वार्तालाप विकसित करने के हमारे यत्न में शुरूआती कदम है, दुर्भाग्यवश यह वार्तालाप पिछले कई वर्षों से कार्यसूची में शामिल नहीं था। हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे विदेश सचिव निकट भविष्य में एक बार पुनः बैठक करेंगे ताकि वे सभी पहलु तैयार किये जा सकें जिनके आधार पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। हमें स्पष्ट लाइन लगाने, दोनों पक्षों द्वारा सहमति के बिना किसी भी निर्णय को अमान्य मानने, रूकावटों को दूर करने की आवश्यकता जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच प्रतिपक्षीय प्रचार-प्रसार को

हो तथा उन बयानों को जिनसे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है, को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।

नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मेरी मुलाकात से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मैत्री की पुनः पुष्टि हुई। इस बात पर सहमति हुई कि मुझे शीघ्र ही सम्भवतः आगामी मास के शुरू में ही नेपाल की यात्रा करनी चाहिए। इसी प्रकार बंगलादेश की प्रधान मंत्री के साथ मेरी मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही। हमारे दोनों देशों के बीच संबंध काफी विकसित हुए हैं और हमने परस्पर सहयोग को बहुत मजबूत बनाया है। हमने जल बंटवारे से संबद्ध संधि की महत्वपूर्ण घटना की क्रियान्वयन की समीक्षा की जिसका क्रियान्वयन नदी में जल की अप्रत्याशित कमी के बावजूद पहले शुष्क मौसम में सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

भारत के घनिष्ठ मित्र महामहिम भूटान नरेश से बातचीत के अवसर का मैंने स्वागत किया है। घर वापस लौटते हुए वे दिल्ली में रुके और इस दौरान उनसे बातचीत करने का मुझे और अवसर मिला।

इसी तरह श्रीलंका की महामान्य राष्ट्रपति के साथ संबंधों के पुनः नवीकरण को मैंने बहुत महत्व दिया। हमने कई मसलों पर विचार विमर्श किया। आजादी के पचासवें वर्ष के अवसर पर अगले वर्ष श्रीलंका में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन की ओर हमारी नजरें लगी हुई हैं।

अन्त में मालदीव के महामहिम राष्ट्रपति श्री गयूम के साथ मेरी दोस्ताना बातचीत हुई। माले में भारतीय सहयोग की परियोजनाओं, एक अस्पताल और प्रशिक्षण केन्द्र, जो दोनों ही अच्छी तरह चल रहे हैं, का दौरा करके मुझे अत्यन्त खुशी हुई।

मुझे आशा है कि इस संक्षिप्त वक्तव्य से यह स्पष्ट होगा कि इस क्षेत्र में हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे उत्कृष्ट संबंध हैं। जहां समस्याएं हैं, वहां हमने जो प्रक्रिया अपनाई है, मुझे विश्वास है कि उसके परिणाम भविष्य में अच्छे ही निकलेंगे।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, क्या प्रधान मंत्रीजी किराया कानून के बारे में स्टैंटमेंट देंगे? ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा। जब मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा, आप धैर्य क्यों नहीं रखते?